समाचार पत्रों की अर्थनीति

आधुनिक केसरी

वसंत मुंडे

महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ मुंबई

प्रदेश अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ, मुंबई

वसंत माधवराव मुंडे

शिक्षा: : **बी.ए.बी.जे.**
(डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद)

पद : प्रदेश अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ, मुंबई (2020)
अध्यक्ष, औरंगाबाद मंडल अधिस्वीकृती समिति (2015)

कार्यरत : 2003 से दैनिक लोकसत्ता के बीड़ जिला प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत। उससे पूर्व कॉलेज में पढ़ते हुए मराठवाड़ा साथी और लोकपत्र से हुई पत्रकारिता की शुरुआत।

विशेष :
* खोजी श्रेणी में उस्मानाबाद मराठी पत्रकार संघ का प्रथम पुरस्कार।
* उपेक्षित दलितों, गन्ना श्रमिकों के लेखन के कारण समर्थन धर्मार्थ संस्था की छात्रवृत्ति।
* 2007 में, प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने ग्रामीण विकास कार्यान्वयन कानून पर तब देश से आमंत्रित चयनित पचास पत्रकारों में सम्मेलन हेतु चयन।
* जिला पत्रकार संघ की ओर से इतिहास शोधार्थी एवं वरिष्ठ संपादक स. मा. गर्गे के नाम नाम से पिछले दस वर्षों से दिए जा रहे राज्यस्तरीय पत्रकारिता पुरस्कार योजना सहित गर्गे स्मारक का निर्माण।
* दैनिक लोकसत्ता के माध्यम से तीन करोड़ रुपये से अधिक नकद राशि एकत्रित कर बीड जिले के वंचित, उपेक्षित वर्गों के लिए काम करने वाली चार सामाजिक संस्थाओं को सहायता।

इस में
* इन्फेंट इंडिया (बीड), एचआईवी प्रभावित बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था है।
* आत्महत्या करने वाले किसानों और गन्ना मजदूरों के बच्चों के लिए काम कर रही शांतिवन (अर्वी) संस्था।
* मूक वन्यजीवों के लिए कार्यरत 'सर्पराज्ञी परियोजना (तगड़गांव)'
* अनाथों के लिए कार्यरत सहारा अनाथालय संस्थान (गेवराई)

१) कृषि पर समग्र और सुसंगत लेखन, प्रमुखता से उन किसानों की सफलता की कहानियाँ जिन्होंने उपलब्ध परिस्थितियों और संसाधनों के आधार पर घाटे में चल रही कृषि से लाभ कमाया है। दो वर्षों में पचास से अधिक ऐसे किसानों को खोजने के बाद, लोकसत्ता के 'लोकशिवार' से उनकी सफलता पर प्रचुर मात्रा में लेखन। किसानों की आत्महत्या का विषय बढ़ने पर स्थिति का सफलतापूर्वक मुकाबला करने वाले किसान मार्गदर्शक बन गए। सरकार की नीति और किसानों की स्थिति पर लगातार प्रकाश डाला है।

२) विभिन्न क्षेत्रों में सफलतापूर्वक काम करने वाले लोगों को चर्चा के माध्यम से समाज के सामने लानने से, बहुत से लोगों को प्रेरणा मिली और अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहन मिला।

३) ग्रामीण क्षेत्रों में, धार्मिक सप्ताहों पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं जब कि गाँव में स्कूल भवन, पीने के पानी और यहाँ तक कि सड़कों की कमी होती है। सटीक रूप से इस सामाजिक व्यंग्य पर प्रहार करते हुए कई गांवों में स्कूल भवन की मरम्मत और सामग्री के लिए धन जुटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। 'धार्मिक गढ़ों की अर्थनीति' और 'गाँवों में मूलभूत सुविधाएँ नहीं होने पर भी "धार्मिक सप्ताहों में भोजन पर करोड़ों का व्यय" विषय यह प्रस्तुत किया।

४) शासन और प्रशासन पर उंगली उठाते हुए सुधारों का सुझाव देने वाली खबरों का सकारात्मक प्रभाव

५) तीन वर्षों से मासिक व्याख्यान श्रृंखला गतिविधि।

६) औरंगाबाद मंडल पत्रकार अधिस्वीकृती समिति महाराष्ट्र सरकार के अध्यक्ष के रूप में अवसर मिलने के बाद प्रशासन औरपत्रकारों के बीच संवाद के लिए 'खुली चर्चा' उपक्रम हर जिले में संपन्न हुआ।

७) महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ के माध्यम से राज्य में रक्तदान शिविर लगाकर डेढ़ हजार बैग रक्त का संग्रह।

८) अखबारों की अर्थनीति और पत्रकारों की समस्याओं पर राज्यव्यापी गोष्ठियों के माध्यम से जागरुकता।

विशेष संपादकीय

वसंत मुंडे : जिन्होंने अखबारों को आर्थिक आत्मनिर्भरता की राह दिखाई

डॉ. प्रभू गोरे, संपादक

पत्रकारिता आम जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का माध्यम है। यही जानकर वसंत मुंडे नाम का युवक पत्रकारिता में आया और आम लोगों के सवाल उठाते हुए अखबारों और पत्रकारों के भी सवाल उठाने लगा! पढ़कर हैरानी हो सकती है, लेकिन वसंत मुंडे ने सोलह साल की उम्र से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा दी थी। छात्र रहते हुए ग्राम रोजगार गारंटी योजना में मजदूरों की अशिक्षा का फायदा उठाकर सामाजिक वनीकरण कार्य में आर्थिक धोखाधड़ी की गयी। उन्होंने दै. 'लोकमत' के अंबाजोगाई के तत्कालीन पत्रकार मोटेगांवकर सर को मजदूरों के इस भ्रष्टाचार के बारे में बताया और न्याय दिलाया।

बाद में पत्रकारिता की औपचारिक शिक्षा के बाद उन्हें दैनिक लोकसत्ता में जिला प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया और वसंत मुंडे वहां 20 वर्षों से कार्यरत हैं। कलम के माध्यम से वंचित और उपेक्षित तबकों के लिए काम करने वाली कई संस्थाओं को आर्थिक मदद पहुंचाई। उन्होंने कृषि और शिक्षा के विषयों पर काफी सकारात्मक और ऊर्जावान लेख लिखे। इसी कारण से तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा आमंत्रित चुनिंदा पचास पत्रकारों की नेशनल कांफ्रेंस में भी श्री. मुंडे निर्वाचित हुए थे। गन्ना मजदूरों के साथ रहते हुए लिखी लेखमालिका 'समर्थ' ने उन्हें को छात्रवृत्ति दिलाई। इसके अलावा भी कई अवॉर्ड मिले। अच्छा संवाद और किसी विषय को बिना समझौता किए चंद शब्दों में प्रस्तुत करने की क्षमता उनकी विशेषता है।

सवाल पूछे, रास्ता बताया

आम लोगों के सवालों को कलम से उठाते हुए साथी पत्रकारों के सवालों को भी महसूस किया. समाज की समस्याओं को सामने रखने वालों की समस्याओं पर अक्सर आंखें मूंद ली जाती हैं। शासकों और समाज को भी नहीं लगता कि पत्रकारों के पास कोई सवाल है। मुंडे ने इस बात को महसूस करने के बाद पत्रकारों के संघ के माध्यम से पत्रकारों और संपादकों के सवाल उठाए और उन्हें हल करने के तरीके भी सुझाए। औरंगाबाद संभागीय अधिस्वीकृति समिति के अध्यक्ष बनने के बाद मुंडे ने महाराष्ट्र में पहली बार प्रत्येक जिले में सरकारी समिति के पत्रकारों के साथ सीधे खुला परिचर्चा कार्यक्रम किया. इससे दमनकारी शर्तों में ढील दी गई और स्वीकृति पत्र प्राप्त करने की राह आसान हो गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर ध्यान दिया क्योंकि शहर से लेकर ग्रामीण स्तर तक के पत्रकारों के सवाल हल किए जा रहे थे।

संपादक न होते हुए भी बने अध्यक्ष

वसंत मुंडे को सर्वसम्मति से महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ (मुंबई) का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। संस्था के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जो संपादक नहीं है ऐसे पत्रकार को अध्यक्ष चुना गया है। अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने तेरह हजार से अधिक पत्रकार सदस्यों वाली संस्था के कार्य को जनोन्मुख बनाने के लिए आधुनिक तरीकों का प्रयोग किया।

आत्मनिर्भरता पर संपादकों का गोलमेज सम्मेलन

सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव से संकट में पड़ा अखबार कारोबार कोरोना की वजह से और मुश्किल हो गया है। विज्ञापनों का प्रवाह कम होने से चेन अखबारों समेत छोटे अखबारों का आर्थिक हिसाब बिगड़ गया है। उत्पादन लागत के तीस प्रतिशत पर अखबारों की होम डिलीवरी की पारंपरिक नीति, कोरोना, ऑनलाइन पढ़ने की आदत से आर्थिक संकट पैदा हो गया और कार्यरत पत्रकारों को वेतन कटौती का सामना करना पड़ा। बहुत से लोगों को नौकरी भी गँवानी पड़ी। ऐसे में वसंत मुंडे ने औरंगाबाद में संपादकों का पहला गोलमेज सम्मेलन किया और अखबारों से आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का आग्रह किया। पिछले 20 साल में पेट्रोल 30 रुपये से 120 रुपये और डीजल 16 रुपये से 97

रुपये प्रति लीटर हो गया। एक रुपए की चाय दस रुपए की हो गई। कागज की छपाई 25 रुपये से 100 रुपये हो गई। जैसे ही सरकार ने विज्ञापन और अन्य वस्तुओं पर 5 प्रतिशत जीएसटी और अन्य कर लगाए, कीमतें पांच गुना बढ़ गईं। जहां ऐसी तमाम चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, वहीं अखबारों के दाम एक गुना भी नहीं बढ़े हैं। आज भी 8 से 12 पेज के अखबार 2 से 5 रुपए में घर पर डिलीवर हो जाते हैं। इसलिए, यह दुनिया का यह एकमात्र उत्पाद है जहां बिक्री मूल्य उत्पादन लागत का 20 प्रतिशत है। चूंकि कम विज्ञापन के कारण घाटे को पूरा करना असंभव था, बिक्री मूल्य में वृद्धि के गणित ने पत्रिकाओं के मालिकों, संपादकों और वितरकों को आश्वस्त किया। पत्रकार भागवत तवारे द्वारा लिखित 'समाचार पत्रों का अर्थशास्त्र' पर वसंत मुंडे के साथ एक साक्षात्कार प्रकाशित किया गया था और राज्य के तीन सौ से अधिक समाचार पत्रों ने इसका समर्थन किया था। परिणामस्वरूप राज्य में तीन सौ से अधिक दैनिकों ने अपने विक्रय मूल्यों में वृद्धि की। जैसा कि यह पहली बार था जब किसी पत्रकार का एक साक्षात्कार विभिन्न दैनिकों में प्रकाशित हुआ था, मुंडे के नेतृत्व को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था।

साप्ताहिक अवकाश लें, फायदे में रहें!

अखबार के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार अखबारों की खरीद पर करदाताओं को सालाना पांच हजार की आयकर छूट दे यह माँग वसंत मुंडे इन्होंने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड़ से की है और इस संबंध में सकारात्मक सोच चल रही है। पहले सूचना के अन्य माध्यम न होने के कारण समाचार पत्रों के नियमित प्रकाशन की नीति भी प्रचलित हो गई थी। लेकिन अब जबकि अन्य साधन उपलब्ध हैं तो समाचार पत्रों को भी रविवार की छुट्टी लेनी चाहिए। सरकार ने अब पांच दिन का सप्ताह भी पेश किया है। प्राइवेट इंडस्ट्री में भी छुट्टियां हैं। इस विचार को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने अवकाश के माध्यम से समाचार पत्रों के आर्थिक लाभ और कर्मचारियों के स्वास्थ्य की गणना की। कुछ दैनिक समाचार पत्रों द्वारा इसे अपनाने के अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। नई पहल के माध्यम से अच्छे परिणाम मिल रहे हैं।

नए उपक्रमों द्वारा आश्वासक माहौलः

वर्षों से सरकार से मांग करने से क्या हासिल हुआ है? यह सोचकर वसंत मुंडे ने न केवल यह भूमिका प्रस्तुत की कि मीडिया के लोग ही सक्षम हो जाएं, बल्कि पत्रकार संघ के माध्यम से नई परंपराएं आरंभ की। कोरोना काल में 28 जिलों में पत्रकारों से वेब संचार के माध्यम से जनभागीदारी से पत्रकारों को किराना सामग्री उपलब्ध करायी गयी. पत्रकार संघ की ओर से जिला प्रशासन को एंबुलेंस उपलब्ध कराई गई। उन्होंने एक ही दिन में पूरे राज्य में रक्तदान शिविर लगाकर 1400 बैग रक्त एकत्रित करने का कीर्तिमान स्थापित किया। सोशल मीडिया के बीच भी संवाद बना रहे इसके लिए औरंगाबाद मंडल कार्यालय में वर्कलाप शुरू किया गया और बीड में मासिक व्याख्यानमाला शुरू की गई. नतीजा यह है कि संघ के माध्यम से प्रदेश भर में वार्ता की जा रही है। दिवाली में स्नेहमेलन और रमजान में ईद मिलन कर टीम को नई दिशा देने की कोशिश की। टीम ने जनभागीदारी से मृत पत्रकारों के परिवारों को सहायता प्रदान करने के साथ-साथ चिकित्सा उपचार के लिए भी सहायता प्रदान की। इस तरह की एक नई पहल के माध्यम से, मुंडे ने संगठन और समाचार पत्र क्षेत्र में नई परंपराओं को सामने लाकर इस क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए एक सहायक वातावरण तैयार किया है।

पांच मंडल सम्मेलन

अखबारों के अर्थशास्त्र और पत्रकारों की समस्याओं पर औरंगाबाद में संपादकों का गोलमेज सम्मेलन, लातूर, ठाणे, नागपुर, जलगाँव में विभागीय सम्मेलनों ने अखबारों के अर्थशास्त्र पर जागरूकता पैदा की है। यह पहली बार था कि अखबारों के अर्थशास्त्र पर स्वतंत्र सम्मेलन न केवल महाराष्ट्र में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए गए थे।

महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ, मुंबई के नागपुर में आयोजित दूसरे विदर्भस्तरीय सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष वसंत मुंडे, महासचिव विश्वास आरोटे, विदर्भ अध्यक्ष प्रो. महेश पानसे, श्रीकृष्ण चांडक, डॉ. श्रीपाद अपराजित, भास्कर लोंढे, सुदर्शन चक्रधर, शब्बीर अहमद विद्रोही आदि मौजूद थे।

समाचार पत्र अपनी पारंपरिक आर्थिक नीति में बदलाव कर आत्मनिर्भर बनें : वसंत मुंडे

संपादकों के गोलमेज सम्मेलन में मुद्दे के विक्रय मूल्य को बढ़ाने पर सहमति

आर्थिक संकट से जूझ रहे अखबार की अर्थव्यवस्था को भी कोरोना से नुकसान हुआ और मशीनों को भी। अब अखबारों को अपनी परंपरागत वित्तीय नीति बदलनी होगी और आत्मनिर्भर बनना होगा। उसके लिए अखबार के अंक का मूल्य बढ़ाना होगा और गुणवत्ता में सुधार करना होगा। महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष वसंत मुंडे ने राय व्यक्त की कि समाचार पत्रों को तभी आर्थिक स्थिरता मिलेगी। राज्य में पहले गोलमेज सम्मेलन में, संपादकों ने मूल्य वृद्धि पर मुद्दे के रुख का स्वागत और समर्थन किया।

महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ मुंबई संभागीय कार्यालय की ओर से पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष वसंत मुंडे की उपस्थिति में राज्य के समाचार पत्रों के संपादकों का पहला गोलमेज सम्मेलन औरंगाबाद में आयोजित किया गया. इस मौके पर दैनिक पुढारी के संपादक धनंजय लांबे, सकाळ के कार्यकारी संपादक दयानंद माने, पुढारी के इकाई प्रमुख कल्याण पाण्डे, लोकपत्र के कार्यकारी संपादक रवींद्र तहकीक, सम्मेलन के संयोजक और पत्रकार संघ के औरंगाबाद जिलाध्यक्ष प्रो. डॉ. प्रभु गोरे, वरिष्ठ संपादक संतोष मनुरकर, संघ के मंडल संयोजक वैभव स्वामी, राज्य मीडिया समन्वयक भगवान राऊत सहित औरंगाबाद, जालना, अहमदनगर जिले के चालीस समाचार पत्रों के संपादक उपस्थित थे। सम्मेलन का शुभारंभ समाचार पत्रों का पूजन कर किया गया। इस मौके पर बोलते हुए वसंत मुंडे ने कहा कि कम कीमत पर अखबार देने की नीति अपनाई गई। हाल के दिनों में अखबारों की संख्या में इजाफा हुआ है और कम से कम कीमत पर अखबारों की होम डिलीवरी का चलन खपत बढ़ाने और विज्ञापन हासिल करने के लिए शुरू हो गया है। यह एक तथ्य है कि समाचार पत्र क्षेत्र खराब वित्तीय समय का सामना कर रहा है क्योंकि विज्ञापन राजस्व में गिरावट आई है। इसलिए संपादकों और पत्रकारों को अखबार की कीमत बढ़ाने और पाठकों को गुणवत्तापूर्ण समाचार पत्र उपलब्ध कराने के लिए पारंपरिक वित्तीय नीति की मानसिकता को बदलने की जिम्मेदारी लेनी होगी। तभी अखबार आर्थिक रूप से सक्षम होंगे।

समय आ गया है कि पाठकों को इस बात से अवगत कराया जाए कि यदि कोई समाचार पत्र पारंपरिक तरीके से चलाया जाता है तो उसे लंबे समय तक घाटे में चलाना संभव नहीं होगा। अखबारों के कागज, स्याही और छपाई की लागत हाल के दिनों में दोगुनी हो गई है। लेकिन पिछले कई सालों से अखबार 2 से 5 रुपए में बिक रहा है। यह धंधा भारी घाटे में करना पड़ रहा है। मध्यकाल में अनेक राजनीतिज्ञों, उद्यमियों तथा पूँजीपतियों ने अपने विभिन्न लाभों के लिए समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारम्भ किया। लेकिन इस क्षेत्र में स्थिरता लाने की जिम्मेदारी किसी ने नहीं उठाई है। मुंडे ने यह भी कहा कि हम सभी को अब वह भूमिका निभानी होगी।

संपादक धनंजय लांबे ने कहा, जब आर्थिक गणित गलत हुआ तो उसका दैनिक मराठवाड़ा जैसा हाल होता है। इसलिए अब समाचार पत्रों की वित्तीय नीति को बदलने के लिए अखबार मालिकों को इस अभियान में भाग लेना होगा। हमें अपना मान बढ़ाना है और सभी को गुणवत्तापूर्ण तरीके से काम कर अपनी क्षमता सिद्ध करनी है, इसके लिए उन्होंने निराशा को दूर कर नए जोश के साथ काम करने का आग्रह किया, जबकि संपादक दयानंद माने ने कहा कि समाचार चैनलों और सोशल मीडिया की भूमिका से अखबारों की खपत पर दूरगामी प्रभाव पड़ा है। डिजिटल मीडिया पर नजर रखते हुए अखबार को बदलते हालात में टिके रहने के लिए नए जोश और नई रणनीति के साथ काम करना होगा। कल्याण पांडे ने जहां अखबारों का वित्तीय गणित बहुत ही सरल तरीके से पेश किया, वहीं कोरोना के बाद बड़ी शृंखला वाले अखबारों और मंडल व जिला दैनिकों की समस्या जस की तस है। कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे-जैसे विज्ञापन पाने के लिए खपत बढ़ती है, घाटा बढ़ता जाता है। ऐसे में अब सभी को कीमतें बढ़ाने के बारे में सोचना होगा।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यदि इसके लिए सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाए तो इस क्षेत्र को फिर से वित्तीय स्थिरता मिल सकती है। संपादक रवींद्र तहकीक ने मीडिया क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक पत्रकार को विधान परिषद में नियुक्त करना चाहिए, साथ ही अखबारों ने कीमत बढ़ाकर समाज में अपनी साख बनाने की अपील की।

इस अवसर पर निमंत्रक प्रो. डॉ. प्रभु गोरे ने परिषद की भूमिका प्रस्तुत की। उन्होंने कहा की अब तक समाचार पत्रों ने समाज के सभी वर्गों की समस्याओं को हल करने के लिए अपनी शक्ति को दाँव पर लगाया है। लेकिन अब जब अखबार ही संकट में है तो सबको साथ आना होगा और इस क्षेत्र को सशक्त बनाने का फैसला लेना होगा। अब हमें संघटित होने के लिए यह परिषद है। अखबारों के लिए कठीण समय में कीमत बढ़ाना यही उचित पर्याय है ऐसा पत्रकार संघ के महानगर अध्यक्ष अनिल सावंत इन्होंने कहा।

अखबारों की कीमत बढ़ाकर, गुणवत्ता सुधारकर आत्मनिर्भर होने प्रयास करना चाहिए। सरकारने अखबारों को कागज और स्याही की कीमत में सहुलियत देनी चाहिए। जीएसटी में छूट दी जाए। समाचार पत्र क्षेत्र को लघू उद्योग का दर्जा दिया जाए। विभागीय एवं जिला दैनिकों को सरकार के अधिक से अधिक विज्ञापन देने के लिए एबीसी को अनिवार्य किया जाए। कोरोना के दौरान शहीद हुए पत्रकारों को घोषित पचास लाख रुपये के बीमा कवर के तहत मदद की जाए। गोलमेज सम्मेलन में आवास एवं स्वास्थ्य बीमा योजना को समुचित ढंग से लागू कर पत्रकारों को सहयोग प्रदान करने की मांगों के प्रस्ताव परिषद में पारित किए गए।

मेट्रो न्यूज के संपादक मकरंद घोड़के, अहमदनगर घडामोडी के संपादक मनोज मोतियानी, नगर स्वतंत्र के संपादक सुभाष चिंध्ये व कार्यकारी संपादक सुभाष मुदळ, लाभवार्ता के संपादक मनोज पाटनी, दै. 'बदलता महाराष्ट्र' के संपादक विष्णु कदम, दै. राज्यवार्ता के संपादक भरत मानकर, लाइव महाराष्ट्र के कृष्णा लोखंडे, वृत्त टाइम्स के संपादक कल्याण अन्नपूर्ण, बहुजन हिताय के बबन सोनवणे, लोक प्रशासन के प्रशांत पाटील, निळे प्रतीक के संपादक रतन कुमार साळवे, आकाश सपकाळ, जगन्नाथ सुपेकर, दै. सत्यनीति के संपादक देवीदास कोळेकर, पुलिस न्यूज के संपादक कृष्णा कोल्हे, अशोक वानखेडे, रमाकांत कुलकर्णी, अभिजित हिरप, पुण्य नगरी के डॉ. शेषराव पठाडे, दै. महानगरी के अशोक देढे, लातूर पॅटर्न के गोविंद काळे आदि परिषद में उपस्थित थे।

परिषद की सफलता के लिए सचिव दीपक मस्के, आयोजक विलास शिंगी, कोषाध्यक्ष मुकेश मुंदड़ा, प्रचार प्रमुख जॉन भालेराव, महासचिव शिवाजी गायकवाड़, महानगर उपाध्यक्ष हनुमंत कोल्हे, बी. आर. इवेंट्स के ऋषिकेश राऊत, अभिषेक राऊत आदि ने मेहनत की।

प्रारंभ में कोरोना के दौरान शहीद हुए पत्रकारों और वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। सम्मेलन के संयोजक प्रो. डॉ. प्रभु गोरे ने स्वागत किया और परिचय दिया। राज्य मीडिया समन्वयक भगवान राऊत ने विभिन्न संकल्प पढ़े। संचालन प्रचार प्रमुख सचिन अंभोरे ने किया। जिला उपाध्यक्ष छाबुराव ताके ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।

महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ मुंबई और दैनिक मराठवाड़ा साथी के सहयोग से पत्रमहर्षि स्व. मोहनलालजी बियाणी राज्य स्तरीय पत्रकारिता पुरस्कार वितरण। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड द्वारा समाचार पत्र शिक्षा विभागाध्यक्ष डॉ. दिनकर माने को सम्मानित किया गया। साथ में क्षेत्रीय अध्यक्ष वसंत मुंडे, प्रधान संपादक चंदूलाल बियाणी, जगदीश बियाणी, मनीषा भन्साली, सतीश लोढ़ा।

अखबार खरीदने वालों को इनकम टैक्स में छूट देंगे : डॉ. भागवत कराड

मराठवाड़ा के व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में अवसर मिलने के बाद सभी ने उसका सदुपयोग किया, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी वसंत मुंड़े ने राज्य भर में पत्रकारों का एक मजबूत संगठन बनाया है और इस क्षेत्र की समस्याओं को हल करने के तरीके भी बताए हैं। मुझे केंद्र में वित्त राज्य मंत्री पद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से मिला। जिस प्रकार लोकतंत्र में समाचार पत्र समाज को जगाकर दिशा देने का कार्य करता है, मैं केंद्र में मिले अवसर से महाराष्ट्र में पत्रकारों की समस्याओं के समाधान की पहल करता रहूंगा। वसंत मुंडे की मांग के अनुरूप एक महत्वपूर्ण घोषणा की जाएगी. समाचार पत्र खरीदने वाले आयकर दाताओं को प्रति वर्ष पांच हजार रुपये छूट देने का प्रयास किया जाएगा यह महत्त्वपूर्ण घोषणा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड द्वारा की गई। रविवार, 16 जनवरी की शाम औरंगाबाद यहाँ महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ मुंबई और दैनिक मराठवाड़ा साथी के सहयोग से पत्रमहर्षि स्व. मोहनलालजी बियाणी राज्य स्तरीय पत्रकारिता पुरस्कार वितरण केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड के हाथों संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अध्यक्ष पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष वसंत मुंडे के साथ प्रधान संपादक चंदूलाल बियाणी, जगदीश बियाणी, मनीषा भंसाली, सतीश लोढ़ा उपस्थित थे। इस मौके पर बोलते हुए डॉ. कराड ने कहा, महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ के क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में वसंत मुंडे के चुनाव के बाद, राज्य भर में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से पत्रकारों को प्रोत्साहित करना, उनकी समस्याओं को हल करना इन गतिविधियों को करने से संगठनात्मक कार्य में वृद्धि हुई है। मैं केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पत्रकार संघ के कार्यक्रम में कई बार आया हूं। मुंड़े ने पत्रकारों और अखबारों की समस्याओं के समाधान के उपाय भी बताए हैं। लोकतंत्र में अखबार और पत्रकार समाज को जगाने और उसका मार्गदर्शन करने का काम कर रहे हैं। इसलिए इन तत्वों की समस्याओं के समाधान के लिए हमारी पहल बनी रहेगी। साथ ही केंद्र सरकार की विभिन्न आर्थिक योजनाओं से पत्रकारों व उनके परिवारों को लाभान्वित करने की पहल करेंगे। पत्रकार केंद्र सरकार की योजनाओं का अध्ययन कर उसका लाभ उठाने का प्रयास करें ऐसी अपील उन्होंने की। कोरोना

वसंत मुंडे का प्रयास सफल रहाः

महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ, मुंबई के क्षेत्रीय अध्यक्ष वसंत मुंडे ने अखबार को आर्थिक नुकसान से उबारने के लिए अखबार की कीमत बढ़ाने समेत कई अहम भूमिकाओं को लगातार आगे बढ़ाया है। साथ ही समाचार पत्र खरीदने वालों को आयकर से छूट मिलनी चाहिए यह माँग जारी रखी। शास्त्रशुद्ध तरीके से समझाया कि इस कर छूट से सरकार को भी फायदा होगा कि यदि यह रियायत दी जाती है तो रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार के ध्यान में यह भी लाया गया कि अखबार के कारोबार में क्रांतिकारी बदलाव आएगा, इसलिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड ने इस कार्यक्रम में अहम ऐलान किया। वसंत मुंडे की मांग को अभूतपूर्व सफलता मिली है। जब कर राहत का फैसला वास्तव में लागू होगा तो अखबार के कारोबार में आर्थिक क्रांति का एक नया युग शुरू होगा और इसका श्रेय मराठवाड़ा के इन दोनों सपूतों को जाएगा।

प्रतिवर्ष 5 हजार रुपये रिटर्न देने का विचार

के बाद अखबार कारोबार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। डिजिटल मीडिया के उदय के बावजूद समाज में समाचार पत्रों की विश्वसनीयता अभी भी बनी हुई है। इसलिए सरकार के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाचार पत्र व्यवसाय को वित्तीय मजबूती दें। इसके लिए वसंत मुंडे की मांग के अनुरूप हम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से चर्चा कर 100 करोड़ रुपये की मांग को मंजूरी देंगे। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि पत्रकार संघ एक समिति बनाकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव सौंपे। दूसरी ओर, वसंत मुंडे ने अखबार व्यवसाय के सामने आने वाली वित्तीय कठिनाइयों और पारंपरिक नीति पर स्पष्ट रुख रखा और मांग की कि केंद्र सरकार पत्रकारों और समाचार पत्रों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए समाचार पत्र खरीदने वाले करदाताओं को कर में राहत दे, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इसी तरह जब तक पत्रकार आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होगा तब तक वह ठीक से काम नहीं कर पाएगा। इसके लिए सरकार को रणनीतिक फैसला लेना चाहिए और अखबार क्षेत्र की मदद करनी चाहिए। चंदूलाल बियाणी ने प्रस्तावना में दैनिक मराठवाड़ा साथी की प्रगति की समीक्षा कर श्री मोहनलालजी बियाणी की स्मृतियों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन श्रवण गिरि, प्रशांत जोशी ने किया और धन्यवाद ज्ञापन संदीप बेद्रे ने किया। विलास शिंगी, मुकेश मुंदडा, राधेश्याम झंवर, सचिन शेरे, वृषाली पेंढारकर, सविता खांडेकर, राहुल राठी, मनोज पाटणी, संजय व्यापारी, माजिद खान, सचिन पवार, तुकाराम राऊत, शिवानंद चक्करवार, पांडुरंग जाधव आदि ने कार्यक्रम की सफलता के लिए मेहनत की। इस अवसर पर राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त प्रो. डॉ. दिनकर माने (विभागाध्यक्ष, जनसंचार और समाचार पत्र अध्ययन विभाग, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद), डॉ. बबन जोगदंड (प्रभारी अधिकारी, यशदा, पुणे), संतोष मानुरकर (संपादक दै. दिव्य लोकप्रभा, बीड) सहित अन्य कई पत्रकारों को पुरस्कार प्रदान कर केंद्रीय मंत्री डॉ. भागवत कराड़ के हाथों सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार बाबा गाडे, प्रकाश भगनुरे, डॉ. संजीव कुमार सावले, डॉ. संध्या मोहिते, संतोष शिंदे, राम वायभट आदि सहित विभिन्न दैनिकों के पत्रकार उपस्थित थे।

म्हाडा के तहत पत्रकारों के लिए आवास निर्माण हेतु विशेष समूह की योजना बनाई जाएगी

आवास मंत्री जितेंद्र अव्हाड ने आवास विभाग के सचिव को आदेश दिया है कि म्हाडा के तहत एक विशेष समूह बनाकर पूरे राज्य में पत्रकारों के लिए आवास योजना को लागू करने के लिए कैबिनेट के समक्ष एक प्रस्ताव रखा जाए। महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष वसंत मुंडे ने मंत्री आव्हाड से मुलाकात कर विस्तार से चर्चा की और पत्रकारों के लिए अलग से योजना लागू करने पर जोर दिया। महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ के राज्य संयोजक संजय भोकरे, प्रदेश अध्यक्ष वसंत मुंडे ने आवास मंत्री जितेंद्र आव्हाड को लिखित बयान के माध्यम से जिला और तालुका स्तर पर म्हाडा के तहत मुंबई और सोलापुर की तर्ज पर पत्रकारों के लिए अलग समूह बनाकर आवास योजना लागू करने की मांग की। विगत कई वर्षों से लगातार विभिन्न संगठन, पत्रकार आवास की मांग कर रहे हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में म्हाडा के तहत जगह की कमी के कारण इन योजनाओं को लागू करने में मुश्किलें आती हैं। 'आदर्श' घोटाले के बाद पत्रकारों के लिए आवास का मुद्दा लंबित है क्योंकि सरकार ने निजी आवास संस्थाओं को जगह नहीं देने की नीति अपनाई है। इस संबंध में आवास मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने मामले को पूरी तरह समझा है और प्रदेश भर में ऐसी नीति बनाने का निर्णय लिया है, जिससे प्रदेश के पत्रकारों को भी आवास मिल सके। जिला और तालुका स्तर

महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ की मांग पर मंत्री जितेंद्र आव्हाड की प्रतिबद्धता।

पर आवास मंत्री अव्हाड ने सचिव को आदेश दिया है कि राजस्व, नगर पालिका एवं जिला परिषद के स्वामित्व वाली भूमि को म्हाडा को हस्तान्तरित कर पत्रकारों की आवास योजना को मांग के अनुरूप क्रियान्वित करने का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष लाया जाये। मंत्री आव्हाड के इस रुख ने महाराष्ट्र में पत्रकारों के लिए आवास के मुद्दे को बल दिया है।

महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ, मुंबई के मराठवाडा क्षेत्रीय संमेलन में उपस्थित ऑल इंडिया जर्नलिस्ट असोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक वानखेड़े, प्रदेश अध्यक्ष वसंत मुंडे, राष्ट्रसंत एकनाथ महाराज, प्रदेश संगठक संजय भोकरे, प्रदेश महासचिव विश्वास अरोटे, संरक्षक संतोष मनुरकर, संजय जेवरीकर, यशवंत भंडारे आदि।

समाचार पत्रों को विक्रय मूल्य बढ़ाकर ही सक्षम होना पड़ेगा: वसंत मुंडे

सरकार से मांग करने के बजाय बदली हुई स्थिति में एक स्थानीय समाचार पत्र और पत्रकारों को आर्थिक रूप से सक्षम बनने के लिए पारंपरिक नीति को बदलना होगा। सस्ते समाचार पत्र उपलब्ध कराकर घाटे की भरपाई के लिए विज्ञापन पर निर्भर रहने के दिन अब लद गए हैं। दस वर्षों में सभी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। सरकार ने तरह-तरह के टैक्स लगाए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ, मुंबई के क्षेत्रीय अध्यक्ष वसंत मुंडे ने राय व्यक्त करते हुए कहा कि समाचार पत्रों को विक्रय मूल्य बढ़ाकर सशक्त बनाना होगा।

रविवार, 28 नवंबर को लातूर में महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ के मराठवाड़ा संभागीय सम्मेलन में वे बोल रहे थे। इस अवसर पर अखिल भारतीय पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक वानखेड़े, राष्ट्रसंत एकनाथ महाराज, राज्य संगठक संजय भोकरे, प्रदेश महासचिव विश्वास आरोटे, संरक्षक संतोष मनुरकर, संजय जेवरिकर, उप निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क लातूर यशवंत भंडारे, मंडल अध्यक्ष वैभव स्वामी, मंडल सचिव दीपरत्न निलंगेकर, मंडल उपाध्यक्ष दयानंद जडे, संयोजक लातूर जिलाध्यक्ष अशोक देडे समेत सभी जिला अध्यक्ष, पदाधिकारी, सदस्य, पत्रकार बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस मौके पर आगे बोलते हुए प्रदेश अध्यक्ष वसंत मुंडे ने कहा कि पत्रकार लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं. लेकिन चूंकि सरकार इसे बहुत गंभीरता से नहीं ले रही है, इसलिए पत्रकारों के सवाल सालों से लंबित हैं। कोरोना काल में सरकार ने पत्रकारों के साथ-साथ स्वास्थ्य और पुलिस कर्मियों को बीमा कवरेज देने की घोषणा की थी। लेकिन इसे अमल में नहीं लाया गया। यह सार्वजनिक धोखाधड़ी है। इसलिए स्थानीय स्तर के अखबारों और पत्रकारों को सरकार से मांग करने के बजाय बदली हुई स्थिति में आर्थिक रूप से सक्षम बनने के लिए पारंपरिक नीति को बदलना होगा। सस्ते समाचार पत्र उपलब्ध कराकर घाटे की भरपाई के लिए विज्ञापन पर निर्भर रहने के दिन अब लद गए हैं। दस वर्षों में सभी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। सरकार ने तरह-तरह के टैक्स लगाए हैं। ऐसे में अखबारों को बिक्री मूल्य बढ़ाकर इससे निपटने में सक्षम होना होगा। संपादकों के गोलमेज सम्मेलन के बाद महाराष्ट्र में दो सौ दैनिकों ने मूल्य में वृद्धि की। दूसरों ने भी अब यही करना चाहिए । अन्य प्रबंधन की तरह समाचार पत्र भी सप्ताह में एक दिन छुट्टी लेकर खर्च बचाएं और कर्मचारियों आराम दें ऐसी अपील उन्होंने की। दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक वानखेड़े ने कहा कि कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट के जजों को मीडिया के सामने आकर अपना दुख व्यक्त करना पड़ा। अतः भारतीय लोकतंत्र में यद्यपि शासक, प्रशासन, न्याय और मीडिया की चार व्यवस्थाएँ प्रमुख हैं, फिर भी पत्रकारों का प्रभाव सबसे अधिक है। सत्ता में बैठे लोगों को भी पता होना चाहिए कि सवाल सिर्फ सत्ताधारियों से ही पूछे जाते हैं। ईमानदार पत्रकारों से सत्ताधारी भी डरते हैं। सरकार में शासकों को अक्सर मीडिया पर निर्भर रहना पड़ता है। पत्रकार समाचारों से राजनीतिक नेताओं का निर्माण करते हैं। अगर वे पत्रकारों को महत्व नहीं देते हैं, तो पत्रकारों में भी उन्हें उनकी जगह दिखाने की क्षमता होनी चाहिए। लातूर के स्वर्गीय विलासराव देशमुख, बीड के गोपीनाथ मुंडे, नांदेड़ के शंकरराव चव्हाण ने देश का नेतृत्व किया। वे आम आदमी और पत्रकारों से जुड़े हुए थे। उन्हें पत्रकारों की ताकत का पता था। इसलिए, मौजूदा स्थिति में, हर देशमुख, विलासराव नहीं होता, हर मुंडे, गोपीनाथराव नहीं होता, हर चव्हाण, शंकरराव नहीं होता है ऐसी तिखी टिप्पणी उन्होंने की।

इस प्रथम मंडल बैठक को सफल बनाने के लिए औरंगाबाद जिलाध्यक्ष डॉ. प्रभु गोरे, ग्रामीण अध्यक्ष शांताराम मगर, जालना जिला अध्यक्ष दिगंबर गुजर, परभणी जिला अध्यक्ष विलास चव्हाण, हिंगोली जिला अध्यक्ष प्रद्युम्न गिरिकर, नांदेड़ जिला अध्यक्ष डॉ. भास्कर भोसले, उस्मानाबाद जिला अध्यक्ष धनंजय पाटील, बीड जिला उपाध्यक्ष नागनाथ जाधव ने लिए परिश्रम के कारण मराठवाड़ा के तालुका और ग्रामीण क्षेत्र से पत्रकार अधिवेशन में भाग लेने आए थे। इसलिए विभागीय स्तर पर यह पहला अधिवेशन ऐतिहासिक हो गया।

महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ, मुंबई का सोलहवां राज्य स्तरीय सम्मेलन ठाणे में संपन्न हुआ। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील को सम्मानित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे, महासचिव विश्वास आरोटे तथा कोंकण मंडल अध्यक्ष नितिन शिंदे।

समाचार पत्रों के वित्तीय सशक्तिकरण को आगे बढ़ाएंगे: केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटील

मीडिया का प्रभाव कम होने से लोकतंत्र कमजोर होगा, इसलिए समाज को खुद मीडिया की उपयोगिता को पहचानना चाहिए और अखबारों की मदद करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील ने पत्रकारों से अपील करते हुए कहा कि पत्रकार भी बिना किसी के कहने पर सही खबर दें, जिससे भरोसा बढ़े। मराठी अखबारों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए वसंत मुंडे ने जो काम किया है वह काबिले तारीफ है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि वे समाचार पत्रों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए केंद्र सरकार के साथ आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ, मुंबई का सोलहवां राज्य स्तरीय अधिवेशन प्रदेश अध्यक्ष वसंत मुंडे की अध्यक्षता में मंगलवार 28 दिसंबर को गडकरी रंगायतन सभागार, ठाणे में दो सत्रों में संपन्न हुआ। विगत दो वर्षों से पत्रकार संघ का राज्य अधिवेशन कोरोना वैश्विक महामारी के कारण टाला जा रहा था। लेकिन इस वर्ष पत्रकारों के आग्रह पर कोरोना नियमों का पालन करते हुए प्रदेश अध्यक्ष वसंत मुंडे के सशक्त नेतृत्व में सोलहवां राज्य अधिवेशन ठाणे में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। क्षेत्रीय अध्यक्ष वसंत मुंडे ने कोरोना काल में अखबारों व पत्रकारों के समक्ष उत्पन्न हुई समस्याओं का सीधे उनसे मिल कर, ऑनलाइन चर्चा कर, संपादकों का गोलमेज सम्मेलन कर विभागीय सम्मेलन के माध्यम से अध्ययन किया। इसलिए इस सम्मेलन के दोनों सत्रों में समाचार पत्र उद्योग की समस्याओं और समाधान पर चर्चा की गई और उपस्थित पत्रकारों को लगा कि भविष्य में सकारात्मक रूप से कार्य करने की ऊर्जा उन्हें मिली है। सत्र का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील ने किया। इस मौके पर महासचिव विश्वास अरोटे, कार्यकारी अध्यक्ष राकेश टोळ्ये, मनीष केत, नितिन जाधव सहित सभी विभागाध्यक्ष व प्रदेश भर से पांच सौ से अधिक पत्रकार उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए, कपिल पाटील ने मराठी पत्रकारिता के इतिहास और वर्तमान स्थिति की ओर इशारा किया। पत्रकारों की हत्याओं और गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए उन्होंने पत्रकारों के सामने आने वाले खतरों के बारे में बताया। लोकतंत्र की इमारत मजबूत है क्योंकि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होते हैं। बदलते हालात में अगर मीडिया का प्रभाव कम होगा तो लोकतंत्र खुद कमजोर हो जाएगा। इसलिए समाज को स्वयं माध्यम की उपयोगिता को पहचानना चाहिए और समाचार पत्रों की मदद करनी चाहिए। पत्रकार भी किसी के कहने पर समाचार न देते हुए सही जानकारी दें, इससे समाचार पत्रों पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा। किसी के कहने पर उनके बारे में दी हुई दो खबरों का उदाहरण देकर उन्होंने पत्रकारिता में गलत बात पर भी अपनी राय रखी। लेकिन अपवाद के साथ, समाज केवल पत्रकारों के कारण ही प्रबुद्ध है। इसलिए उन्होंने ध्यान रखने की अपील की कि प्रबोधन की मार्केटिंग न हो इसका भी ध्यान रहे। पाटील ने राज्य पत्रकार संघ के कार्यों की सराहना की और मांगों को केंद्र स्तर पर मदद करने का आश्वासन दिया।

अखबार बेचने की पारंपरिक निति बदलने से ही मराठी अखबारों स्थिरता मिलेगी
- प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे

मराठी अखबार तभी स्थिर होंगे जब बिक्री जारी करने की परंपरागत नीति बदली जाए। पत्रकार संघ के क्षेत्रीय अध्यक्ष वसंत मुंडे ने अपना पक्ष रखते हुए पत्रकारों की समस्याओं को विस्तार से बताया। उन्होंने कोरोना के बाद क्षेत्रीय अखबारों के सामने आ रही चुनौतियों को पेश करते हुए कहा कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए अखबारों को सस्ते में बेचने की परंपरागत रणनीति में बदलाव करना चाहिए और ऐसा होने पर ही इस क्षेत्र में काम करने वालों को रोजगार की स्थिरता मिलेगी। अंत में उन्होंने पत्रकार टीम के वर्ष भर के कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। महासचिव विश्वास आरोटे और कोंकण मंडल अध्यक्ष नितिन शिंदे ने प्रस्तावना की।

नागपुर में आयोजित विदर्भ स्तरीय दूसरे सम्मेलन में भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री विलासराव मुत्तेमवार, प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे, महासचिव विश्वास आरोटे, उमरेड के विधायक राजू पारवे, श्रीकृष्ण चांडक आदि उपस्थित थे।

महंगाई के अनुसार अखबार का विक्रय मूल्य बढ़ना चाहिए: विलासराव मुत्तेमवार

पहले अखबार को चलाने के लिए भारी प्रयास और पूंजी लगाने के बावजूद इस उद्योग को चलाना चुनौतीपूर्ण था। अब आधुनिक मशीनरी की उपलब्धता से समाचार पत्रों के स्वरूप में जबरदस्त बदलाव आया है। हालाँकि, एक अखबार की कीमत महंगाई के अनुरूप नहीं बढ़ी है। इस क्षेत्र के सामने कई समस्याएं खड़ी हो गई हैं। इसलिए अंक की कीमत महंगाई की तुलना में बढ़ाई जानी चाहिए" यह बात कही पूर्व केंद्रीय मंत्री विलासराव मुत्तेमवार ने। महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ, मुंबई के सहयोग से रविवार, 24 अप्रैल को नागपुर में दूसरा विदर्भ स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष वसंत मुंडे, महासचिव विश्वास आरोटे, उमरेड के विधायक राजू पारवे, दैनिक ओशन समाचार पत्र के संपादक श्रीकृष्ण चांडक सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

आज भी अखबार उद्योग चलाना मुश्किल होता जा रहा है। एक छोटे से गांव में दो, चार, छह, बारह पन्नों का अखबार चलाना एक कठिन काम है। फिर भी, समाचार पत्र उद्योग में पत्रकार और संपादक कागज की कीमत और महंगाई बढ़ने पर भी दो-पांच रुपयों में घर तक समाचार पत्र पहुँचाते हैं। विलासराव मुत्तेमवार ने अपना दैनिक शुरू किया था, जिसका उद्घाटन भारत के पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने किया। जिसे उन्होंने प्रतियोगिता के कारण ग्यारह वर्षों तक चलाया। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों और अखबार उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों का जिक्र किया। उन्होंने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की कि इलेक्ट्रॉनिक युग में, विशेष रूप से आज के टेलीविजन चैनलों में तत्काल समाचारों की मांग समाचार पत्रों के प्रसार को कम कर रही है।

महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष वसंत मुंडे ने अपने अध्यक्षीय भाषण में पिछले दो वर्षों में महामारी के कारण कई पत्रकारों की असामयिक मृत्यु पर चिंता व्यक्त की। मुंडे ने कहा कि कोरोना के दौरान देशवासियों तक खबरें पहुंचाने के लिए दिन-रात काम कर हजारों पत्रकारों ने अपनी जान गंवाई। कई पत्रकारों की नौकरी जाने के बाद भी सरकार ने फ्रंटलाइन वॉरियर्स को सुविधाएं नहीं दी।

विश्वास आरोटे ने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के पत्रकारों को साथ लाने का काम महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ ने किया है। हम समाज के उत्तरदायी है इसी भाव को ध्यान में रखते हुए राज्य पत्रकार संघ कोंकण मंडल में 365 दिनों से विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया था तब भारी बारिश के समय 6 ट्रक अनाज व अन्य सामग्री का वितरण किया। साथ ही कोरोना काल में पूरे प्रदेश में गरीब लोगों को किराना व अन्य सामग्री का वितरण भी किया। राज्य सरकार पत्रकारों को 50 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान करेगी ऐसा स्वास्थ्य मंत्री मा. राजेश टोपे ने पुणे में कहा था। कोरोना से 325 पत्रकारों की मौत हुई है। लेकिन सरकार ने किसी पत्रकार और उनके परिवार की मदद नहीं की बल्कि राज्य पत्रकार संघ ने मृतक पत्रकारों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की। देश के वित्त मंत्री डॉ. भागवत कराड ने विभिन्न मंत्रियों के साथ बैठक भी की और कहा कि राज्य पत्रकार संघ की ओर से यह काम किया जाएगा कि पत्रकारिता के साथ-साथ पत्रकारों को व्यवसाय कैसे दिया जा सकता है। राज्य सरकारने कोरोना योद्धा के तौर पर सबको सम्मनित किया लेकिन इस ज़रूरत को नजरअंदाज किया। राज्य पत्रकार संघ ने कोरोना काल के योद्धाओं का विशेष सम्मान करते हुए उनके कार्य की सराहना की। इस वक्त विश्वास आरोटे ने कहा की, उपेक्षित वर्ग के कार्य को जानकर उन्हें पत्रकार संघ की ओर से सम्मानित किया जाता है।

दूसरे सत्र में प्रदेश अध्यक्ष वसंत मुंडे, दैनिक महासागर के संपादक श्रीकृष्ण चांडक, दैनिक महाराष्ट्र टाइम्स के संपादक श्रीपाद अपराजित, दैनिक लोकशाही वार्ता के संपादक भास्कर लोंढे, दैनिक राष्ट्र प्रकाश के संपादक सुदर्शन चक्रधर, एनसीपी के नेता शब्बीर अहमद विद्रोहि ने पत्रकारों का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम की सफलता के लिए विदर्भ के पूर्व अध्यक्ष प्रो. महेश पानसे, महासचिव शरद नागदेव, विदर्भ संयोजक आनंद शर्मा, नागपुर जिलाध्यक्ष प्रदीप शेंडे, विदर्भ उपाध्यक्ष अनूप कुमार भार्गव, चंद्रपुर जिलाध्यक्ष सुनील बोकडे के अलावा विदर्भ अध्यक्ष बालासाहेब देशमुख, फरहीन शाह, रोहिल्ला बेग, सुरेंद्र कश्यप, मो. ई. डॉ. सुधीर कमलाकर व अन्य ने सहयोग किया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन मोहम्मद सलीम ने किया जबकि नीलेश सोमाणी ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया।

महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ, मुंबई मुंबई के उत्तर महाराष्ट्र संभागीय सम्मेलन जलगाँव में संपन्न हुआ। इस मौके पर जल आपूर्ति मंत्री तथा पालक मंत्री गुलाबराव पाटील को सम्मानित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे, महासचिव विश्वास आरोटे आदि।

अखबारोंके वित्तीय मामलोंपर मंत्रिमंडल में चर्चा करेंगे: मा. गुलाबराव पाटील

राजनेता और पत्रकार समन्वय से काम करेंगे तो राज्य के विकास को गति मिलेगी, महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष वसंत मुंडे की मांग के अनुसार पत्रकारों को गैर-सरकारी समितियों पर नियुक्त करने पर सकारात्मक विचार किया जाएगा यह कहते हुए जल आपूर्ति मंत्री एवं पालक मंत्री गुलाबराव पाटील ने आश्वासन दिया कि वह कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे को उठाने का प्रयास करेंगे और राज्य भर के पत्रकारों को विभिन्न समितियों में शामिल करेंगे। पत्रकार संघ के क्षेत्रीय अध्यक्ष वसंत मुंडे ने राय व्यक्त करते हुए कहा कि कोरोना के बाद की स्थिति में पाठकों को भी अपनी मानसिकता तैयार करनी होगी ताकि अखबारों का विक्रय मूल्य बढ़े और वित्तीय स्थिरता बने।

महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ मुंबई उत्तर महाराष्ट्र संभागीय अधिवेशन मजदूर दिवस 1 मई को जलगाँव में जल आपूर्ति मंत्री एवं पालक मंत्री गुलाबराव पाटील की उपस्थिति में एवं पत्रकार संघ के क्षेत्रीय अध्यक्ष वसंत मुंडे की अध्यक्षता में दो सत्रों में संपन्न हुआ। इस अवसर पर पत्रकार संघ के क्षेत्रीय महासचिव विश्वास आरोटे, विधायक सुरेश भोले (राजुमामा), महापौर श्रीमती जयश्री महाजन, पूर्व मंत्री गुलाबराव देवकर, कलेक्टर अभिजीत राउत, पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रवीण मुंडे, मनोकल्प के निदेशक मनोज वाणी, मंगलग्रह संस्थान के अध्यक्ष दिगंबर महाले आदि उपस्थित थे। इस मौके पर बोलते हुए मंत्री गुलाबराव पाटील ने कहा कि पत्रकारों के कारण ही राजनीतिक कार्यकर्ता बनते हैं। स्थानीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक पत्रकारों के माध्यम से शासकों की गलतियों को दिखाने और समाज को दिशा देने का कार्य किया जाता है। इसलिए राजनेता और पत्रकार समन्वय से काम करें तो प्रदेश के विकास को गति दी जा सकती है। मेरे व्यक्तित्व विकास में पत्रकारों की अहम भूमिका है। संकट की घड़ी में मराठी पत्रकार संघ विभिन्न माध्यमों से पत्रकारों की मदद के लिए तैयार है। इसलिए संघ के प्रदेश अध्यक्ष वसंत मुंडे की मांग के अनुसार स्थानीय स्तर पर सरकारी और अर्धसरकारी समितियों में पत्रकारों को अशासकीय सदस्य के रूप में नियुक्ति देने पर सकारात्मक विचार किया जाएगा। वहीं, गुलाबराव पाटील ने आश्वासन दिया कि वे पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और उन्हें राज्य भर की विभिन्न समितियों में मौका देंगे। पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष वसंत मुंडे ने कहा कि कोरोना की सबसे बड़ी मार अखबार क्षेत्र पर पड़ी है और विज्ञापन कारोबार में आई कमी तथा अखबारी कागज व अन्य वस्तुओं के दाम बढ़ने से लोगों को सस्ते में अखबार उपलब्ध कराना मुश्किल हो गया है। नतीजतन अखबार में काम करने वाले पत्रकारों व अन्य कर्मचारियों का रोजगार अस्थिर हो गया है।

देश भर में अखबारों का चालीस हजार करोड़ का कारोबार दस हजार करोड़ का हो गया है। इसलिए अन्य देशों की तरह समाचार पत्रों को अस्थिरता को रोकने के लिए उत्पादन लागत के सापेक्ष समाचार पत्रों के विक्रय मूल्य में वृद्धि करनी चाहिए। तभी अखबार क्षेत्र में काम करने वाले पत्रकारों और कर्मचारियों को स्थिरता मिलेगी। समाचार पत्र में काम करने वाला राज्य और देश में एक बड़ा वर्ग है। उन्होंने सरकार से इस वर्ग की समस्याओं और कठिनाइयों को अलग से समझने और कोई रास्ता निकालने की अपील की। कोरोना काल में महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ की ओर से लगभग डेढ़ करोड़ रुपये मूल्य के खाद्यान्न व अन्य सामग्री का वितरण प्रदेशभर के गरीब लोगों को किया गया। भारी बारिश के कारण महाड़, चिपलून, रत्नागिरी, ठाणे जिलों को काफी नुकसान हुआ, राज्य पत्रकार संघ की ओर से वहाँ छह ट्रक सामग्री दी गई। पत्रकार संघ के राज्य प्रचार प्रमुख नवनाथ जाधव, मराठवाड़ा अध्यक्ष वैभव स्वामी, मराठवाड़ा संचार प्रमुख कुंडलिक वालेकर, संजय फूलसुंदर, डिप्टी मेयर कुलभूषण पाटील, शालिग्राम गायकवाड़, मुकुंद नन्नावरे, प्रवीण सपकाले, किशोर रायसाकडा, प्रमोद सोनवणे, मिलिंद लोखंडे, जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजपूत, जगदीश सोनवणे, प्रदीप गायके, दीपक सपकाले, शरद कुलकर्णी, भूषण महाजन, नाजनीन शेख, भगवान मराठे, संजय चौधरी, कमलेश देवरे, विलास ताठे, भानुदास चव्हाण, विजय गाड़े, महेंद्र सूर्यवंशी, गोपाल सोनवणे एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अयाज़ मोहसिन ने किया।

मीडिया की अर्थनीति पुन: परिभाषित करने वाला नेतृत्व

संतोष कानडे

बीड यह सिर्फ गन्ना मजदूरों या बेरोजगारों का जिला नहीं है, बल्कि नेतृत्व करने वालों का जिला है। इस मिट्टी में नेतृत्व के बीज जन्म से ही हैं ऐसा प्रतीत होता है। 'अध्ययन करके दुनिया के सामने आने' का व्रत लेकर चलने वालों की संख्या कम ही सही लेकिन निश्चित है।

बीड पत्रकारों का भी जिला है। यहां बहुत सारे पत्रकार रोजगार की तलाश में हैं, न्याय के तलबगार हैं और अपना नाम बनाने की कोशीश में हैं। ये सब पहले खुद से और फिर व्यवस्था से लड़ रहे हैं। यह लड़ाई एक जमाने में व्यर्थ और बिना सूत्र की थी। वसंत मुंडे ने इन संघर्षों को एक सूत्र में बांधा।

करीब बीस साल पहले पत्रकारिता में आए वसंत मुंडे का नाम पूरे प्रदेश में पहुंच गया है। यह नाम पत्रकारों के प्रश्न और उन्हें सुलझाने की कला की वजह से है। 'कला' शब्द इसलिए लिखा है कि केवल इच्छा होने से या समय देने से काम नहीं होता है। जागरूकता पैदा करने और समस्याओं को हल करने के लिए एक व्यक्ति को कौशल की आवश्यकता होती है। वह वसंतजी मुंडे में है। उन्होंने अब यह साबित कर दिया है कि अगर आपका 'बेसिक' पक्का है तो छोटे उपाय भी बड़े कारगर हो सकते हैं। राजनीतिक संगठन उतने तकलीफ देने वाले नहीं होते जितने पत्रकारों के संगठन होते हैं। क्योंकि पत्रकार हमेशा सवाल उठाने और उंगली उठाने की भूमिका में होते हैं।

प्रश्न जानकर संघर्ष की योजना:

वसंत मुंडे ने महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ के माध्यम से जिलाध्यक्ष पद से कार्य आरंभ किया। बाद में, वे मराठवाड़ा अध्यक्ष, राज्य कार्यकारी अध्यक्ष और अब राज्य सरकार अधिस्वीकृति समिति के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। इसी के जरिए पत्रकारों के सवाल उनके समझ में आए और लड़ाई शुरू हो गई। पत्रकारों की मानसिक स्थिरता से लेकर आर्थिक स्थिरता तक की उनकी लड़ाई सफलता की राह पर है। वह भी प्रदेश के प्रमुख दैनिक लोकसत्ता में काम करते हुए।

यह समय ऐसा है कि किसी को विश्वास नहीं होता कि पत्रकारों की समस्याएं होती हैं, दैनिकों की भी समस्या हो सकती हैं या पत्रकारिता में अस्थिरता आदि हो सकती है। यह इसलिए एक धारणा है कि लड़ाई, न्याय, अन्याय, सवाल, मांग... इन शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ खबरों में होता है। दूसरों को छोड़िए लेकिन पत्रकारों का भी यही हाल है। जैसे दीए तले अंधेरा हो। लेकिन अगर किसीने इस बात पर जोर दिया है कि 'पत्रकारों की भी समस्याएं हैं और उनका समाधान होना चाहिए', तो वे वसंत मुंडे हैं। पत्रकार खुद भूखा हो तो दूसरे का क्या भला करेगा? यह सीधा-साधा गणित है। लेकिन किसी के गले नहीं उतर रहा था। क्या अन्याय के साये में जीने वाला दूसरों को न्याय दे सकता है? क्या उसके प्रयास वास्तव में ईमानदार होंगे? यह असली सवाल पूछने की धमकी मुंडेजी में है। आज स्थिति बदल रही है। पत्रकार, छोटे-छोटे अखबार, मीडिया हाउस जागरूक हो रहे हैं, पत्रकारिता के अर्थशास्त्र का पहिया रफ्तार पकड़ने वाला है. वसंत मुंडे के प्रयास सराहनीय हैं और निश्चित रूप से फल देंगे।

सबको साथ लेकर चलने वाला सक्षम नेतृत्व:

हर क्षेत्र में संगठन होता है। नेता होते हैं। राजनीति विज्ञान की कसौटी के अनुसार नेतृत्व का एक पैर संगठन की ओर और दूसरा प्रगति की ओर उठना चाहिए। तभी वह संस्था, वह समाज उन्नति कर सकता है। दोनों पैर समाज में या संगठन में हो तो नहीं चलेगा। या फिर दोनों पैरों का विकास की दिशा में चलना भी ठिक नहीं। साथ लेकर चलने की अवधारणा सक्षम नेतृत्व की जिम्मेदारी बताने वाली है। वसंत मुंडे का नेतृत्व उतना ही कुशल है। इसलिए वे छोटे अखबारों के पत्रकारों की समस्याएं लेकर मुंबई-दिल्ली के चक्कर लगाते हैं। क्या होते हैं पत्रकारों के प्रश्न? अपर्याप्त पारिश्रमिक, काम के घंटे तय न होना, अनिर्धारित भोजन का समय, स्वास्थ्य सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं और पर्याप्त छुट्टियां नहीं। न पैसा है और न परिवार के लिए समय। इस तरह की दुविधा में फंसे पत्रकारों के लिए क्या किया जा सकता है, इसके लिए उनके चल रहे प्रयासों को देखकर उनका प्रयोगात्मक नेतृत्व सिद्ध होता है। अधिस्वीकृति समिति का क्षेत्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मुंडे ने खुली चर्चा का प्रयोग किया। पत्रकारिता के इतिहास में ऐसा प्रयोग आज तक किसी ने नहीं किया। वे राज्य के कई शहरों में गए और वहां पत्रकारों से सीधे संवाद किया। आपके प्रश्न क्या हैं? अधिस्वीकृति प्रमाणपत्र प्राप्त करने में क्या कठिनाइयाँ हैं या दमनकारी नियम क्या हैं? उन्होंने यह पता लगाने के लिए संघर्ष करना शुरू किया कि पत्रकार कैसे आसानी से मान्यता प्राप्त कर सकते हैं और इससे अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उसमें वह सफल भी रहे। उनके कार्यकाल के दौरान वरिष्ठ पत्रकारों को अधिक से अधिक अधिस्वीकृति पत्र मिले। महत्वपूर्ण यह है कि, मुंडे ने अधिस्वीकृति पत्रों के लिए दैनिकों का कोटा बढ़ाने में बहुत योगदान दिया। अतः तालुका स्तर पर कार्यरत पत्रकारों एवं मुख्यालय स्तर पर कार्यरत पत्रकारों को अतिरिक्त 'अधिस्वीकृति' प्राप्त हुई। बेशक, यह सब प्रश्न को समझकर हासिल किया गया था। इसलिए मराठवाड़ा और राज्य के पत्रकार मुंडे के नेतृत्व पर अड़े हुए हैं।

आर्थिक सुधार के लिए ब्लू-प्रिंट:

अगर हम वास्तव में यह समझना चाहते हैं कि मुंडे ने पत्रकारों के लिए क्या काम किया, तो हमें उनके द्वारा प्रस्तुत 'अर्थशास्त्र' या 'नीति' को समझना होगा। तब जाकर मुंडे के ब्लू-प्रिंट को सही मायनों में समझने में मदद मिलेगी।सोशल मीडिया और डिजिटल पत्रकारिता के कारण छोटे-छोटे दैनिक अखबार बंद हो गए हैं। इसमें दो साल का कोरोना का साया था। इससे बेरोजगारी की कुल्हाड़ी पूरे मीडिया जगत पर गिरी। मीडिया घरानों ने बिना किसी कानूनी बंदिश के कर्मचारियों की छंटनी की। छोटे दैनिक समाचार पत्र पूरी तरह से ढह गए। पारिश्रमिक पर काम करने वाले जिला व तालुक के पत्रकार बेहद बेचैन हो गए। ऐसी स्थिति में वसंत मुंडे चुप कैसे रह सकते थे? लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ के माध्यम से विभिन्न पत्रकारिता गतिविधियां शुरू की गई। पत्रकारों का हौसला बढ़ाया। लेकिन मीडिया की दुनिया बनाने के लिए एक स्थायी समाधान की जरूरत थी। मुंडे ने 2020-21 के आसपास दैनिक समाचार पत्रों की कीमतों में वृद्धि के संबंध में एक नया विचार प्रस्तावित किया। सभी ने इसे चौंक कर देखा और अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। कीमतें कैसे बढ़ेंगी?, क्या लोग पेपर खरीदेंगे? इससे क्या हासिल होगा? इस तरह के सवाल आने लगे। इस अवधि के दौरान उन्होंने बैठकों और संचार पर जोर दिया। उन्होंने अपनी बात सरल रखी। वह उन्हें मनाने के लिए घंटों बात करते थे। बाजार में प्रत्येक उत्पाद का अपना मूल्य होता है, जिसे निर्धारित करने का अधिकार निर्माता के पास होता है। कच्चे माल की लागत, जनशक्ति, बिजली, परिवहन, वितरण, इन सभी लागतों को समझ कर फिर उत्पाद का मूल्य निर्धारित करना होता है। ये है बाजार का गणित। लेकिन समाचार पत्र क्षेत्र इससे बेखबर था। मीडिया को अपने मेल्य का कोई एहसास नहीं था। चार पन्ने के एक अंक की कीमत बीस से तीस रुपए, आठ पन्ने के रोज की कीमत पचास-साठ रुपए के आसपास होती है। फिर रोज की कीमत 2-5 रुपए ही क्यों, यही अहम सवाल है। वसंत मुंडे ने इस पर जोर दिया और सारांश प्रस्तुत करना शुरू किया कि 'आहिस्ता-आहिस्ता कीमतें बढ़ाओ, दैनिक खर्च कम होगा तो वित्तीय साक्षरता हासिल होगी'। उसमें वह सफल भी रहे। राज्य में लगभग 150 से 200 दैनिकों ने कीमतें बढ़ाने का फैसला किया और ऐसा किया भी। दिलचस्प बात यह है कि किसी भी दैनिक खपत पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। किसी के अंक कम नहीं किए गए या किसी पाठक द्वारा साधारण सी शिकायत भी नहीं की गई। दैनिक अखबार बहुत सहजता से सक्षम होने लगे। यह अभियान ही शुरू हो गया है। यह अभियान अब पूरे राज्य में फैलने की कोशिश कर रहा है। एक छोटा सा उपाय बहुत ही

कारगर साबित हुआ।

दैनिक समाचार पत्र मजबूत खड़ा होगा तो पत्रकारिता बचेगी, यही मूल सूत्र है। इतना ही नहीं उन्होंने दिल्ली तक आवाज बुलंद की। जिस कार्यालय में दैनिक का पंजीकरण होता है वहां उन्होंने 'आरएनआई' के अधिकारियों को भी दैनिक की कीमत के बारे में समझाया। तब अधिकारी भी आश्चर्यचकित हुए। अब मुंडे ने इस संबंध में अलग से प्रशासनिक या न्यायिक लड़ाई छेड़ दी है। एक बार यह 'रजिस्ट्रार कार्यालय' दैनिक समाचार पत्रों के मूल्य पर एक आधिकारिक निर्णय ले लेता है, तो मीडिया जगत को राख से उठने में देर नहीं लगेगी।

साप्ताहिक अवकाश लें

वसंत मुंडे की अगली बात हैरान करने वाली है। साप्ताहिक अवकाश। 'अख़बार में कोई छुट्टी होती है क्या? छुट्टी छोड़ कर बात करो ऐसी 'प्रतिक्रियाएँ थीं। यहां भी मुंडे ने उसके पीछे का जो अर्थशास्त्र और स्वास्थ्यशास्त्र है उसे मनवा लिया। 'एक दैनिक को छापने और उसे पाठकों के दरवाजे तक पहुंचाने में कितना खर्च आता है? एक दिन का कितना खर्चा आता है? एक महीने में चार दिन और एक साल में 48 दिन की लागत क्या है? ऐसा कोई नियम नहीं है कि दैनिकों में साप्ताहिक अवकाश न हो। एक तो लागत बचाता है और दूसरा कर्मचारियों को खुश रखता है। आज सरकार ने पांच दिन का सप्ताह बना दिया है। कई निजी कंपनियों और कॉर्पोरेट समाचार क्षेत्र में भी पाँच दिन का सप्ताह होता है। तो छोटे दैनिकों और पत्रकारों ने क्या किया? इसके विपरीत, छुट्टी के कारण पत्रकार अधिक ऊर्जा के साथ काम कर पाएगा!' राज्य के कई दैनिक समाचार पत्रों ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। कुछ ने इसके बारे में सोचते हुए छुट्टियां भी शुरू कर दीं। इस फैसले से पत्रकारिता के प्रति अपनापन और आकर्षण पैदा करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही मुंडे ने पत्रकार पेंशन और पत्रकार संरक्षण अधिनियम में बहुत योगदान दिया है।

वसंत मुंडे की मांग है कि केंद्र सरकार जिला दैनिक, लघु संभागीय दैनिक को लघु उद्योग में शामिल करे। इसके लिए उनकी केंद्रीय लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे से बातचीत चल रही है। दैनिक समाचार पत्रों को लघु उद्योग का दर्जा मिलने पर वे उस उद्योग मंडल के अंतर्गत आएंगे। एमआईडीसी क्षेत्रों में प्रिंटिंग मशीन, कर रियायत और प्रिंटिंग प्रेस के लिए जगह के लिए ऋण उपलब्ध हो सकता है। साथ ही उम्मीद है कि बजट में इस व्यवसाय के लिए प्रावधान किया जाएगा। निश्चित तौर पर अख़बार मजबूती से खड़े होंगे। जनता की आवाज और बुलंद होगी। लेकिन इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है। बहरहाल, मुंडे का ईमानदार प्रयास जारी है।

समाचार पत्रों के पाठकों को टैक्स में राहतः

एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है। जिससे दैनिक की खपत बढ़ सकती है। साथ ही अच्छे लेखन को आर्थिक सहयोग मिलेगा। यह मुद्दा है समाचार पत्रों की खरीद पर ग्राहक को कर कटौती मिलनी चाहिए। किसी पाठक ने साल भर अखबार खरीदा तो उसे इन्कम टैक्स रिटर्न में पांच हजार रुपयों की रियायत मिले इस मांग को लेकर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड से वसंत मुंडे ने कई बार मुलाकात की। विचार-विमर्श हो रहा है। अगर सरकार इस फैसले को गंभीरता से लेती है तो दैनिक अखबार मजबूती से खड़े रहेंगे। कम से कम टैक्स छूट से घर में अखबार पढ़ने की परंपरा को बढ़ाने में मदद मिलेगी। अच्छे लेखक आगे आएंगे। पत्रकार एक अध्ययनपूर्ण प्रस्तुति देने के लिए बाध्य होंगे। ये सभी उपलब्धियां सिद्ध की जा सकती हैं। केंद्र सरकार ने अगर तय किया, अगर अच्छे फैसले लिए गए तो दैनिक अखबारों के वीरान महलों के लिए मजबूत दीवारें और छत मिल सकती है। वसंत मुंडे इसके लिए प्रयासरत हैं।

संघर्षशील नेतृत्वः

वसंत मुंडे एक योद्धा हैं जो पत्रकारों के लिए लड़ते हैं। यह एक उदाहरण है कि पत्रकारों का नेतृत्व क्या कर सकता है। सभी पत्रकारों को ईमानदारी से समर्थन देकर वसंत मुंडे का हाथ मजबूत करने की जरूरत है। पत्रकारिता का चेहरा बदले बिना व्यवस्था का चेहरा नहीं बदलेगा। उसके लिए पत्रकार; जिसे चौथा स्तंभ कहते हैं, उसका मजबूत होना जरूरी है। अधिस्वीकृति पत्र मिलने में आसानी, दैनिक समाचार पत्रों की कीमतों में वृद्धि, साप्ताहिक अवकाश, पाठकों को टैक्स रियायतें, दैनिकों को लघु उद्योग का दर्जा, पत्रकारों को अच्छा पारिश्रमिक; वसंत मुंडे इन सभी मोर्चों पर काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उनका काम एक दिन नया इतिहास रचेगा।

अखबार खरीदने वाले करदाताओं को छूट देने का प्रस्ताव केंद्र को भेजेंगे

उपमुख्यमंत्री अजित पवार का पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष वसंत मुंडे को आश्वासन

पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष वसंत मुंडे को उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने आश्वासन दिया कि, महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ की मांग के अनुसार अखबार व्यवसाय को आर्थिक संबल देने हेतु अखबार खरीदने वाले करदाताओं को इन्कम टैक्स में पांच हजार रुपयों की छूट देने का प्रस्ताव राज्य सरकार केंद्रीय वित्त मंत्री को भेजेगी,

शुक्रवार 8 अप्रैल को अंबाजोगाई के महापौर राजकिशोर मोदी के आवास पर महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष वसंत मुंडे, संतोष मानुरकर, वैभव स्वामी ने उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और पालक मंत्री धनंजय मुंडे से मुलाकात की और कोरोना के कारण संकट में पड़े अखबार व्यवसाय के लिए आर्थिक सहयोग की मांग की। पत्रकार संघ के माध्यम से अखबार व्यवसाय को आर्थिक स्थिरता मिलने हेतु केंद्र सरकार ने अखबार खरीदने वालों को सालाना 5 हजार रुपये की छूट देने की मांग सालभर से की जा रही है। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को वसंत मुंडे ने इस मांग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मांग के बारे में तथ्यों को जानने के बाद उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने मांग का स्वागत किया और कहा की राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार को तुरंत एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। पत्रकार संघ को केंद्र सरकार से फालोअप करना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार का पूरा सहयोग रहेगा। पत्रकारों की अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से बात कर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा। विज्ञापन कम होने के कारण और बिक्री मूल्य उत्पादन लागत का केवल तीस प्रतिशत होने के कारण समाचार पत्र व्यवसाय संघर्ष कर रहा है। कागज के दाम बढ़ने से परेशानी और बढ़ गई है। इसलिए अजित पवार को इस बात की जानकारी देकर कि राज्य भर के अखबारों में काम करने वाले पांच लाख लोगों का रोजगार अस्थिर हो गया है, उन्होंने इस व्यवसाय में मदद करने के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। जैसा कि राज्य सरकार प्रस्ताव देगी, पत्रकार संघ की मांगों को और बल मिलेगा।

समाचार पत्रों को लघु उद्योग का दर्जा देने पर विचार करेंगे: केंद्रीय मंत्री नारायण राणे

महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष वसंत मुंडे ने अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के उन मंत्रियों से मुलाकात की जो हाल ही में केंद्र में आए है। उनसे वसंत मुंडे इन्होंने पत्रकारों के विकास के लिए अनुरोध किया। वसंत मुंडे ने नई दिल्ली में अपने निवास पर पत्रकारों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर केंद्रीय लघू उद्योग मंत्री नारायण राणे के साथ विस्तृत चर्चा की। राज्य संपादकों का पहला गोलमेज सम्मेलन सितंबर 2020 में औरंगाबाद में आयोजित किया गया था। इस ऐतिहासिक गोलमेज सम्मेलन में राज्य के संपादकों ने सर्वसम्मति से मराठी अखबार उद्योग को लघू उद्योग का दर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव के अनुसार, वसंत मुंडे ने मांग की कि महाराष्ट्र में क्षेत्रीय और जिला स्तर के समाचार पत्रों को लघु उद्योग का दर्जा दिया जाना चाहिए ऐसी मांग मा. नारायण राणे से की।

इस अवसर पर नारायण राणे ने पत्रकारों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे समाचार पत्र उद्योग को लघु उद्योग का दर्जा देने के संबंध में एक विस्तृत प्रस्ताव दें, इसे वे कैबिनेट बैठक में अवश्य रखेंगे और मंजूरी भी प्राप्त करेंगे।

जिगरी दोस्ती का अनोखा दर्शन

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड तथा सहकारिता मंत्री अतुल सावे, बीड यात्रा के दौरान, उनके पुराने मित्र पत्रकार वसंत मुंडे के कार्यालय गए। शुरुआती दिनों की यादों को ताजा करते हुए मुक्त संवाद शुरू हुआ और जिगरी दोस्तों की महफील जमी। इस समय मुंडे, कराड और सावे के बीच हृदयपूर्वक मित्रता का अनुभव हुआ। सार्वजनिक जीवन में हाल ही में तीक्ष्ण भूमिकाएँ और राजनीति में कुछ ऊँचाइयों तक पहुँचने के बाद व्यक्तिगत मित्रता को सँभालकर रखना एक अपवाद है। लेकिन वह दिखाई दिया।

बीड में शनिवार 10 दिसंबर को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड, सहकारिता मंत्री अतुल सावे आए थे। कार्यक्रम के बाद दोनों ने महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष वसंत मुंडे के कार्यालय को भेंट दी। पिछले बीस वर्षों में वसंत मुंडे ने अपनी उपलब्धियों से पत्रकारिता के क्षेत्र में एक अलग छाप छोड़ी है। तो डॉ. कराड, सावे ने भी राजनीतिक क्षेत्र में विशेष ऊंचाइयां हासिल की हैं। जिस समय कराड और सावे ने राजनीतिक कैरियर का आरंभ तभी वसंत मुंडे ने भी अपनी पत्रकारिता शुरू की थी। भले ही वसंत मुंडे बीड में एक पत्रकार के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन वे शुरू से ही संगठन के माध्यम से पत्रकारों से संपर्क में रहे हैं। स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे, विलासराव देशमुख सहित राज्य भर में पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रसिद्ध लोगों के संपर्क में आने के बाद, अक्सर यह देखा गया कि उन्होंने पत्रकारिता से परे जाकर दोस्ती का एक मजबूत धागा बनाया। संयोग से, हालांकि कराड, सावे और मुंडे अपने-अपने क्षेत्र में एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंच गए थे, बीड़ के लोगों ने महसूस किया कि तीनों ने अपनी व्यक्तिगत मित्रता को प्रभावित किए बिना अपने रिश्ते को बनाए रखा। जैसा कि सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक भूमिकाएं हाल ही में अधिक चरम हो गई है, व्यक्तिगत स्तर पर सहजता कम हो गई है ऐसा दिखाई दे रहा है।

लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद व्यस्त कार्यक्रम के कारण नेताओं के दौरे जल्दबाजी में होते हैं। इसलिए, चाह कर भी मित्रों से मिलना और दिल का रिश्ता विकसित करना संभव नहीं है। ऐसे में मुंडे, कराड और सावे की मुलाकात ने सार्वजनिक भूमिकाओं से परे सौहार्दपूर्ण मित्रता का भावपूर्ण दर्शन कराया। अखबारों के अर्थशास्त्र पर वसंत मुंडे द्वारा बारीकी से किए गए अध्ययन की बुकलेट केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री कराड और सहकारिता मंत्री को दी गई। उस वक्त दोनों ने पत्रकारिता के क्षेत्र में वसंत मुंडे के काम की सराहना की। इस अवसर पर संपादक संतोष मानुरकर उपस्थित थे।